प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 12 – 19 जून 2017 मूल्य पांच रूपए

सरकार और वीरभद्र की व्यक्तिगत हार हैं नगर निगम के चुनाव परिणाम

शिमला/शैल। वीरभद्र को सातवीं बार मुख्यमन्त्री बनाने और कांग्रेस सरकार के पुन: सत्ता में आने के दावों पर नगर निगम शिमला की हार मुख्यमन्त्री और उनके सलाहकारों की टीम के लिये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस हार का सबसे दु:खद निगम क्षेत्र में जुड़े थे उनमें से केवल तीन में ही कांग्रेस को जीत हासिल हो पायी है। इन विधानसभा क्षेत्रों में इतनी बड़ी हार वीरभद्र सिंह के लिये व्यक्तिगत स्तर पर एक बड़ा झटका है क्योंकि शिमला ग्रामीण से वह स्वयं विधायक है और अगला चुनाव यहां से उनका बेटा विक्रमादित्य लड़ना चाहता है। विक्रमादित्य की उम्मीदवारी तो एक तरह से घोषित भी की जा चुकी है। शिमला ग्रामीण के साथ ही कुसुम्पटी भी उनका अपना ही क्षेत्र माना जाता है क्योंकि उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह यहां से ताल्लुक रखती है। इस चुनाव में संजौली ढली क्षेत्र के भी सारे वार्डो में कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है जबकि इन क्षेत्रों में ऊपरी शिमला के लोगों का बाहुल्य है यहां कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाना जिला शिमला को वीरभद्र के लिये एक बड़े संकट का संकेत माना जा रहा है।

नगर निगम शिमला पर 2012 तक कांग्रेस और वीरभद्र का एक छत्र राज रहा है। 2012 में सत्ता सीपीएम के हाथ चली गयी थी। उस समय भी सीपीएम कांग्रेस के एक बड़े वर्ग के सहयोग से सत्ता में आयी थी। सीपीएम और कांग्रेस के अघोषित गठबन्धन के कारण ही माकपा सत्ता में पूरा कार्यकाल काट गयी। इस कार्यकाल में माकपा शासन पर असफलता के ऐसे कई अवसर आये थे जब माकपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे सत्ता से हटाया जा सकता था लेकिन ऐसा नही हुआ। इन चुनावों में भी जब कांग्रेस ने अधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया था तब दबी जुबान से यह चर्चा भी थी कि कांग्रेस के एक धड़े का माकपा से अघोषित गठबन्धन हो गया है। इसी गठबन्धन के कारण माकपा ने केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि उसने हर वार्ड में नये वोटर बनाये थे लेकिन जिन बारह वार्डो में माकपा ने अपने प्रत्याशी नही उतारे थे वहां पर माकपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नही हो पाया। इस तरह जहां माकपा को अपनी असफलताओं का नुकसान उठाना पड़ा और वह केवल एक सीट पर सिमट गयी वहीं पर कांग्रेस को भी इससे सीधे हानि हुई। इस चुनाव परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार न उतारने का पहला फैसला एकदम गलत था। उसके बाद नाम वापसी के अन्तिम दिन प्रत्याशीयों की सूची जारी करके कई वार्डो में अपने प्रत्याशीयों को चुनाव से हटाने में सफल नहीं हो सके। इस चुनाव का प्रबन्धन हरीश जनारथा के पास था लेकिन वह अपने संजौली क्षेत्र में ही बुरी तरह असफल रहे। हर्ष महाजन भी वीरभद्र के बड़े राजनीतिक सलाहकारों में गिने जाते हैं लेकिन वह भी अपने वार्ड में सफलता नहीं दिला पाये। कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु जो स्वयं कभी इसी नगर निगम के पार्षद रह चुके है वह भी अपने वार्ड में असफल रहे है।

इस तरह जहां इस हार के लिये सुक्खु – वीरभद्र का द्वन्द बहुत हद तक जिम्मेदार है। वहीं पर मुख्यमन्त्री के गिर्द बैठे अधिकारियों का वह वर्ग भी पूरी तरह जिम्मेदार है जो कि वीरभद्र की सरकार चला रहा है। क्योंकि आज प्रशासन हर मोर्चे पर बुरी तरह असफल रहा है। इस कार्यकाल में भष्टाचार के जिन मामलों पर विजिलैन्स पूरी तरह व्यस्त रही है। उनमें एक भी मामले को अन्जाम तक नहीं पहुंचा सकी है। विजिलैन्स प्रशासन अपनी असफलता के लिये आज सीधे मुख्यमन्त्री के अपने कार्यालय को दोषी ठहराता है। विजिलैन्स का आरोप है कि कुछ मामलों की फाईले मुख्यमन्त्री के कार्यालय में सालो तक दबी रही हैं। इस कारण जब सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले तो

शेष पृष्ठ 8 पर.....

तिलक राज प्रकरण का ईडी ने भी लिया संज्ञान जारी रही न्यायिक हिरासत

कुछ अधिकारियों और नेताओं तक आ सकती है आंच

शिमला/शैल। पांच लाख के रिश्वत मामलों में एक उद्योगपति के साथ रंगे हाथों सीबीआई द्वारा पकड़े गये हिमाचल उद्योग विभाग के बद्दी स्थित संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा अभी तक न्यायिक हिरासत से बाहर नही आ पाये हैं। सीबीआई के चार दिन के रिमांड के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह चौदह दिन पूरे होने के बाद जब तिलक राज को पुन: अदालत में पेश किया गया तब सीबीआई ने उनकी हिरासत जारी रखने का आग्रह किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया क्योंकि तिलक राज ने स्वयं ही जमानत के लिये याचना नही की थी। तिलक राज ने जमानत के लिये क्यों आवदेन नही किया इस सवाल की पड़ताल में यह सामने आया है कि अब इस प्रकरण का सीबीआई के साथ ही ईडी ने भी संज्ञान ले लिया है।

स्मरणीय है कि जब एक फार्मा उद्योग की सब्सिडी की फाईल प्रौसैस करने के लिये तिलक राज ने अशोक राणा के माध्यम से दस लाख की रिश्वत की मांग की थी और इस मांग की सूचना सीबीआई को दी गयी थी तब सीबीआई ने तिलक राज, अशोक राणा और शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर के बीच इस संद्धर्भ में हो रही बातचीत को रिकार्ड किया था जब उस संवाद में यह सामने आया था कि रिश्वत का यह पैसा मुख्यमन्त्री के दिल्ली स्थित ओएसडी रघुवंशी को जाना है। फिर तिलक राज और अशोक राणा के चार दिन के रिमांड के दौरान सीबीआई को जो जानकारीयां मिली हैं उनमें एक दिल्ली स्थित सुरेश पठानियां का नाम भी सामने आया है। इसके अतिरिक्त दो नेताओं, दो बड़े अधिकारियों और इनके कुछ परिजनों तथा कुछ पत्रकारों के नाम भी सामने आने की चर्चा है जिन लोगों ने अकसर तिलक राज की सवेाओं का लाभ भी उठाया है और उसे संरक्षण भी दिया है। यह सारी जानकारियां मिलने के बाद सीबीआई ने इन सारे लोगों के बारे में आयकर, आईबी आदि के माध्यम से भी पड़ताल की है। इस पड़ताल के बाद ही दिल्ली में रघुवंशी और सुरेश पठानिया से अलग – अलग पूछताछ करने के साथ ही तिलक राज और अशोक राणा को आमने – सामने बैठा कर भी सवाल जवाब किये गये हैं। सूत्रों की माने तो बहुत लोगों की दिल्ली, चण्डीगढ़ और देहरादून तक संपत्तियां होने की जानकारी सामने आयी है।

बद्दी में कुछ फार्मा उद्योगों के लाईसैन्सों को लेकर तथा कुछ स्टोन क्रशरों पर ईडी लम्बे समय से नजर रखे आ रहा था। इसमें उद्योग विभाग के साथ – साथ, पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, तथा स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कन्ट्रोल बोर्ड, तथा स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कन्ट्रोल से जुड़े अधिकारी केन्द्रिय ऐजैन्सियों के राडार पर चल रहे थे कुछ उद्योगों के दस्तावेजों को लेकर तो एक अधिवक्ता की सेवाएं भी ली गयी है। इस अधिवक्ता ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ उद्योगों की प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल उठाये हैं। यह रिपोर्ट भी कुछ उद्योगों द्वारा सब्सिडी लिये जाने के संद्धर्भ में आई है। इस रिपोर्ट के बाद ही ईडी ने करीब डेढ़ दर्जन उद्योगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रखी है। माना जा रहा है कि तिलक राज और उसके संपर्को पर ऐजैन्सीयों की लम्बे समय से नजर चली आ रही थी। अब तिलक राज की गिरफ्तारी और जमानत के लिये आवदेन न करने से यह माना जा रहा है कि यह पूरा प्रकरण काफी लम्बा चलेगा और इसमें आने वाले दिनों में कई लोगों पर गाज गिरेगी।

अब ईडी द्वारा इसका संज्ञान लेने के बाद तथा इस संद्धर्भ में रघुवंशी और सुरेश पठानिया से भी प्रारम्भिक पूछताछ होने से यह माना जा रहा है कि इस मामले में कई बड़े लोगों से निकट भविष्य में पूछताछ की जायेगी तथा कुछ और गिरफ्तारीयां भी हो सकती है।

राज्यपाल ने किया टॉर्च थमाकर ओलम्पिक दौड़ का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवाओं में अधिक से अधिक खेल भावना विकसित करने पर बल दिया ताकि उन्हें नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सके।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल ओलम्पिक ऐसासिएशन द्वारा हिमाचल राज्य ओलम्पिक खेलों के पहले चरण में शिमला से हमीरपुर तक ओलम्पिक टॉर्च (दौड़) के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल देव भूमि है और इसे वीरभूमि भी कहा जाता है तथा जिस प्रकार हिमाचल ओलम्पिक ऐसासिएशन ने इसे खेल भूमि बनाने की ओर कदम बढ़ाया है वह सराहनीय है। उन्होंने एसोसिएशन को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बल्कि उन्हें सुविधाएं और उनमें खेलों के प्रति रूची पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की तथा कहा कि इसका एकमात्र उपाय खेल है। युवा पीढ़ी में जितनी खेल भावना विकसित होगी उतना हम भावी पीढ़ी की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे। उन्होंने आयोजकों के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके यह प्रयास प्रदेश में खेल का नया वातावरण विकसित करने में सहायक होंगे।

इस अवसर पर, सांसद एवं हिमाचल ओलम्पिक ऐसासिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ओलम्पिक टॉर्च सोलन के पांवटा से होते हुए ऊना से गुजरेगी तथा जिस जिले से यह गुजरेगी वहां के स्कूलों के बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। दौड़ में 50 हजार से अधिक बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौड़ में कई पूर्व ओलम्पिक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ''युवा दौड़ेगा तो जीतेगा हिमाचल''।

एशियन कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष जनार्धन गहलोत ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

ओलम्पिक ऐसासिएशन के महासचिव राजेश भण्डारी ने ऐसासिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी।

इसके पश्चात्, राज्यपाल ने ओलम्पिक टॉर्च को रवाना किया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Solan Distt. Solan HP on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on item rate in electronic tendering system, in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/ firms registered with HPPWD dearptment.

S. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of Tender	Eligible class of Contractor
1.	"Special repair to District Hospital Old building at Solan(SH:-Painting & Distempering in roof etc"	12,90,403/-	26,000/-	500/-	"D&C"
2.	"Construction of Gaura Reh-Ka-Katal via Dahar Km 0/0 to 5/500 (SH:Formation cutting in Km.5/0 to 5/500."	12,17,727/-	25,000/-	500/-	"D&C"

2. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website https://hptenders.gov.in.
Bidder would be register in the web-site which is free of cost . For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA) "Aspiring bidders who have not obtained there ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: https://hptenders.gov.in. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates. :-

1. Date of Online Publication :	15.06.2017 at 10.00 Hrs.
2. Document Download Start and End Date	15.06.2017 at 10:30 Hrs upto 06.07.2017 at 10.30 Hrs.
3. Bid Submission Start and End Date	15.06.2017 at 10:30 Hrs upto 06.07.2017 at 10.30 Hrs.
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document.	06.07.2017 upto 10.30 Hrs.
5. Date of Technical Bid opening Evaluation of Technical Bid followed by opening of Financial Bid	06.07.2017 at 11.00 Hrs.

4. Tender Details:-
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.
i) Cover -1 Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"
ii) Cover-2:- Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.

5. SUBMISSION OF ORGINIAL DOCUMENTS:-The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the office **Executive Engineer HPPWD Solan HP** as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date, Failing which the bid will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on 06.07.2017 at 11:00 HRS in the office **Executive Engineer, B&R Division, HPPWD Solan HP** by the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **90 days** after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the biding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even thought the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.- 1094/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय रेड क्रॉस मेले का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि रेड क्रॉस द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पुनीत आन्दोलन आरम्भ किया है और समाज के सभी वर्गों को इस नेक कार्य में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सार्वभौमिक है कि सभी जरूरतमंदों की सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेड क्रॉस गतिविधियों से और अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया, ताकि इसे जन आन्दोलन बनाया जा सके।

राज्यपाल शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्य स्तरीय रेड क्रॉस मेले के शुभारम्भ आर्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से रेड क्रॉस के लिए उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह किया, ताकि गरीब व असहाय लोगों की सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और जिम्मेदार नागरिकों को रेड क्रॉस गतिविधियों से अपने आप को जोड़ना चाहिए।

उन्होंने मेले के दौरान लगे स्टालों का भी अवलोकन किया और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।

आचार्य देवव्रत ने आजीवन सदस्यों, अन्य सदस्यों व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर ढली स्थित पाठशाला के विशेष बच्चों तथा राजकीय पाठशाला बालूगंज व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, टूटू के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

रेड क्रॉड अस्पताल कल्याण शाखा की आवैतनिक सचिव पूनम चौहान ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा रेड क्रॉस की गतिविधियों बारे जानकारी दी।

राज्य रेड क्रॉस सोसायटी के महासचिव पुष्पेन्द्र राजपूत, रेड क्रॉस के सचिव पी.एस. राणा, जिला प्रशासन के अधिकारी, रेड क्रॉस के सदस्य व स्वयंसेवी तथा शहर के गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने किया गौशाला का शिलान्यास

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोलन जिला के अंतर्गत सुबाथू स्थित गौशाला सेवाधाम कठनी में गौशाला का शिलान्यास करते हुए कहा कि आश्रम के आस-पास ही उपयुक्त स्थान पर एक और गौशाला का निर्माण किया जाएगा। यहां उन्नत किस्म की गायों का पालन किया जाएगा और इसे अभियान के तौर पर लिया जाएगा। आचार्य देवव्रत ने कहा कि गौ-पालन हमारी संस्कृति से जुड़ा है और गऊ पालन को धर्म विशेष से जोड़ना गलत है। गऊ हमें स्वास्थ्य के लिए उत्तम अमृत समान दूध देती है। गोबर और गौ मूत्र कृषि के लिए उपयोगी है, जो बंजर जमीन को बचाने का एकमात्र साधन है। इसलिए गौ पालन कर हम संस्कृति से भी जुड़ेंगे तथा स्वास्थ्य के साथ-साथ भावी पीढ़ी को भी स्वस्थ और सुरक्षित कर पाएंगे।

इस मौके पर उन्होंने गौशाला निर्माण के लिए दो लाख रुपए देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जीवन का कुछ उद्देश्य है और वह है धर्म, अर्थ व कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। योग धर्म का मार्ग है और यही ईश्वर प्राप्ति का उचित मार्ग है। उन्होंने कहा कि मानव का निर्माण सबसे कठिन कार्य है तथा इस दिशा में भारतीय संस्कृति ने योग का सूत्र दिया। भारत का चिंतन योग का था तथा साधना और कर्म इस के अभिन्न अंग थे। योग ही सत्य और यथार्थ में ले जाने का मार्ग है और योग जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर उत ष्ठ विद्यार्थियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओ को सम्मानित भी किया।

योग पीठ आश्रम के स्वामी योग तीर्थ ने भी इस अवसर पर योग और संस ति पर अपने विचार व्यक्त किये।

बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एच.सी. शर्मा, उपायुक्त राकेश कंवर, शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी.के. खोसला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'TENDER'

Sealed item rate tenders are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the Executive Engineer , Chopal Division HPPWD Chopalfor the following works from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.P.WD so as to reach in the office on or before 12-07-2017. At 11:00 am And will be opened on the same day at 11:30 a. in the presence of the intending contractors /firms or their authorized representatives who wish to be present. Application for tender form should be submitted to his office (Chopal Division HPPWD Chopal) against cash payment (Non refundable) on any working day during the office hours up to 4:00 PM dated 11.07.2017 and tender documents can be from his office on 10.07.2017 at 11:00am up to 4:00 PM No tender form documents will be issued at ster 4:00 P.M on scheduled dated If the office happens to be closed on the scheduled date the tender form documents will be sold /opened on the next working day at the same time and venue.

The Earnest Money in the shape of FDR NSC purchase from any nationalized Bank or Post Office Shall be deposited duly pledged in favour of the Executive Engineer , Chopal Division HPPWd Chopal , must accompany with application form . conditional tender and the application received without earnest money will summarily be rejected . The offer of the tender shall be opened for 90 days. The XEN reserves the right to reject/accept the tenders without assigning any reason.

The copy of the latest renewal/ enlistment EPF of Labour Act, PAN Number and GST/CST/ TIN number must also accompany the application for the tender documens.

S. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time
1.	M/T on link Road Sarain ti Jhoker Raod to Bijat Maharaj Sarain km RDs 0/ to 1/400(SH: P/L G-I & G-II between km Rds 0/0 to 0/0850)	2,96,507/-	6000/-	350/-	One Month
2.	M/T on link Road Sarain ti Jhoker Raod to Bijat Maharaj Sarain km RDs 0/ to 1/400(SH: P/L G-I & G-II between km Rds0/0 to 0/0850to 1/400)	1,19,861/-	3850/-	350/-	One Month
3.	M/T link road from Dhartu Khari to Pubhal km 0/0 to 3/0 (SH:s P/L G-I between km RDs 0/0 to 2/0)	4,49,498/-	10000/-	350/-	One Month.
4.	C/o Road at Teen Khamba to Kurag at km Rds 0/0 to 1/600 (SH:- C/o R / wall between km Rds 0/407 to 0/424.50)	2,75,479/-	6000/-	350/-	One Month.
5.	C/o Marog Ghareen Teen Khamba Road km Rds 0/0 to 6/500(SH c/o wire created B/wall at km Rds 3/290 to 3/ 320 & 4/308 to 4/338)	1,41,571/-	3000/-	350/-	One Month.
6.	C/o Road at Teen Khamba to Kurag at km Rds 0/0 to 1/600 (SH C/o R/wall between km Rds 1/414 to 1/421	1,83,642/-	4000-/	350/-	One Month.
7.	C/o Road at TeenKhamba to Kurag at km Rds 0/0 to 1/600 (SH : C/o wire crate B/wall between km Rds 0/370 to/ 380 & 0/437.50 to 0/470)	1,34,884/-	2700/-	350/-	One Month.

Adv. No.- 1175/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मैसमराइजिंग मण्डी की तर्ज पर शिमला में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न जिलों के कार्यक्रम

शिमला/शैल। मण्डी जिला के रीति-रिवाजों पर शिमला में मई माह के दौरान आयोजित 'मैसमराइजिंग मण्डी' सांस्कृतिक कार्यक्रम की तर्ज

पर विभिन्न जिलों की कला, शिल्प व परम्पराओं से सम्बन्धित कार्यक्रम आगामी महीनों में शिमला में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित बैठक में मैगा इवैंट की रूपरेखा को अंतिम रुप देने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किन्नौर जिला का मैगा सांस्कृतिक कार्यक्रम जून माह में आयोजित किया जाएगा, जबकि कुल्लू जिले का जुलाई में, लाहौल-स्पिति का अगस्त में तथा चम्बा जिले का सितम्बर, 2017 में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, ऊना तथा हमीरपुर जिलों के मैगा सांस्कृतिक कार्यक्रम आगामी महीनों में आयोजित किये जाएगें।

मैगा इवैंट के दौरान शिमला के गेयटी थियेटर में मनोहर सिंह जयन्ती के आयोजन का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान थियेटर कार्यशाला में थियेटर गतिविधियों से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हास्य कार्यक्रमों के आयोजन को गेयटी थियेटर में आयोजित करने के बजाए, खुले स्थान पर आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने कहा कि शिमला में शीघ्र ही एक हेलिपेड बनाया जाएगा, जिसमें तीन से चार हेलिकाप्टर एक साथ उतारे जाने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सारी औपचारिकताएं पूर्ण ली गई हैं।

भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक शशि ठाकुर ने आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मैगा आयोजनों बारे संक्षिप्त जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविन्द मेहता, डॉ. एस.के. बाल्दी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ऐ.जे.वी प्रसाद, पर्यटन विकास निगम के आयुक्त दिनेश मल्होत्रा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक आर.एस. नेगी, ललित कला अकादमी के प्रशासक सी.एस.कृष्ण सेठी, एन.जेड.सी.सी. के सचिव जगजीत सिंह और कमलेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश कला अकादमी के उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा भी अन्य गणमान्य व्यक्ति के अलावा इस बैठक में उपस्थित थे।

महासंघ ने की होशियार सिंह की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा

शिमला/शैल। वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधी मण्डल महासंघ के अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हि.प्र. तरूण कपूर की अध्यक्षता वन प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन हि.प्र. एस.एस.नेगी की उपस्थिति में सचिवालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित सभी अधिकारीयों व कर्मचारीयों ने मण्डी वन वृत के करसोग वन मण्डल के कटाण्डा बीट प्रभारी होशियार सिंह की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट मौन रखा। महासंघ ने होशियार सिंह की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हि.प्र. अनुरोध किया की इस सुनयोजित हत्या के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए साथ ही मांग की गई एस.आई.टी. व सी.आई.डी. की टीम में सभी अधिकारीयों का ताल्लुक जिला मण्डी से नही होना चाहिए ताकि इस निर्मम हत्या की गुत्थी को निष्पक्ष तरीके से सुलझाया जा सके।

इसके साथ महासंघ ने दिवंगत के परिवार में उसकी अकेली बुढ़ी रह गई दादी मॉ को सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की गई ताकि उनका आगामी जीवन यापन कुछ सरल हो सके। महासंघ ने इसे हिमाचल गौरव या बहादूरी पुरस्कार से सम्मानित करने या शहीद का दर्जा देने की मांग की गई तथा दिवंगत वन रक्षक के नाम से कोई समारक या स्मृति पार्क बनाने की मांग की।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्दों पर भी विचारविमर्श हुआ जिसमें प्रत्येक वन रक्षक के साथ गश्त के लिए एक चौकिदार की व्यवस्था, बीटों के आकार को छोटा (पुर्नगठन) करने बारे, बन्दूकों के स्थान पर लाईट वेट पिस्टल दी जाएगी, नये भर्ती हुए वन रक्षकों को बिना प्रशिक्षण के बीट में नहीं लगाया जाएगा व प्रशिक्षण की उपरान्त भी कुछ समय वरिष्ठ वन रक्षक के साथ अटैच किया जाएगा, वन मण्डल स्तर पर एक बलेरो कैम्पर गाड़ी सामूहिक गश्त वाहन के प्रावधान बारे सहमती बनी, इसके साथ ही सभी फिल्ड कर्मचारीयों को मोबाईल भत्ता दिया जाएगा व प्रत्येक वन रक्षक को वन अधिनियम कानून की हिन्दी में एक-2 पुस्तक वितरीत की जाएंगी। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हि.प्र. ने उपरोक्त मुद्दों पर सहमती जताकर जल्द लागू करने के निर्देश दिए तथा भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न हो इसके लिए हर माह रेंज स्तर पर व तीन माह में एक बार वन मण्डल स्तर पर व छ माह में वन वृत स्तर पर फिल्ड कर्मचारीयों की बैठक उच्चधिकारीयों के साथ करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रशासन विनीत कुमार, संयुक्त सचिव वन सतपाल धीमान, महासंघ सचिव पवन कुमार, शिमला वन वृत महासंघ प्रधान दिनेश शर्मा व सभी वन वृतों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दृष्टिबाधितों के बैकलॉग भरने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में दृष्टिबाधित की सेवाओं संबंधी मामलों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बैकलॉग भरा जाए।

बैठक में सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए कुछ योग्यता से संबंधित मापदण्ड़ों में छूट देने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित भी रिक्त पदों के लिए शामिल किए जाएंगे।

यह भी निर्देश दिए गए कि पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए और दृष्टिबाधितों से संबंधित सभी औपचारिकताएं 31 जुलाई, 2017 तक पूरी की जाएं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर, अरविंद मैहता, ए.जे.वी. प्रसाद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त फैडरेशन के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल समाप्त

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के उपरांत सोलन और बिलसापुर जे.पी. ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने आठ दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल वापिस ले ली। जिला सोलन और बिलासपुर जे.पी. ट्रक ऑपरेटर समन्वय समिति लगभग 27 करोड़ रुपये के ढुलाई शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण हड़ताल पर थी।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे प्रेम ठाकुर, दौलत सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त कैप्टन भगत सिंह ठाकुर और कुलदीप सिंह ठाकुर को जूस पिलाने के बाद ट्रक ऑपरेटरों को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में मधुर औद्योगिक संबंध कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में अनुकूल औद्योगिक परिवेश स्थापित हुआ है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण जे.पी सीमेंट्स की ओर से इस इकाई को बंद करना रहा, जिसे अब अल्ट्रैक सिमेंट्स खरीदने जा रहा है।

उद्योग मंत्री ने समन्वय समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर उनकी पूरी अदायगी की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ऑपरेटरों का भुगतान नहीं हो जाने तक ट्रकों के वित्तदाता उनके ट्रकों को जब्त नहीं करेंगे।

20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने इस मामले के सकारात्मक समाधान के लिए अग्निहोत्री का आभार व्यक्त किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एजेवी प्रसाद, उद्योग विभाग के निदेशक राजेश शर्मा, उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर और पुलिस अधीक्षक राहुल बोध भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जीएसटी के लिए व्यापारियों को तैयार करने हेतु सीआईआई हिमाचल आया सामने

शिमला/शैल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू होने जा रहा है जो मल्टीलेवल इन डायरेक्ट टैक्स के विपरीत प्रभाव को समाप्त करेगा तथा पूरे देश को एक बाजार बनाने में सहायता करेगा। अभी तक की व्यवस्था के तहत अक्सर टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था जो इस व्यवस्था के चलते नहीं देना पड़ेगा। इसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह सहायता करेगा।

जीएसटी को लेकर लगातार हो रही कार्यशालाओं की श्रेणी में भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल ने कार्यशालाओं की एक नई सीरीज 'गेयरिंग उप फॉर चेंज' को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों तथा चंडीगढ़ में आरंभ करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

15 जून को शिमला, 21 जून को ऊना, 22 जून को बद्दी, 23 जून को काला अम्ब तथा 12 जुलाई को चंडीगढ़ में यह कार्यशाला आयोजित की जाएंगी।

कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए सीआईए हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉउंसिल के चेयरमैन राजेश साबो ने कहा उद्योगों को आज यह समझना होगा कि जीएसटी किस प्रकार से प्रभाव डालेगा तथा किस प्रकार की संभावनाएं पैदा करेगा इन सबको समझकर उद्योग जीएसटी से लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी उद्योगो को प्रभावित करेगा चाहे वह क्षेत्र के आधार पर हो या भौगोलिक स्थिति के आधार पर। साबो ने चिंता व्यक्त की वर्तमान में विशेष श्रेणी के तहत विशेष लाभ पाने वाले उद्योग क्षेत्रों को किस प्रकार से जीएसटी के तहत डील किया जाएगा क्योंकि वर्तमान में जीएसटी इन क्षेत्रों को लेकर कैसे छूट प्रदान करेगा इसको लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से वर्तमान में मौजूद रजिस्ट्रेशन तथा माइग्रेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा ट्रांजिशनल प्रोविजन पर स्थिति स्पष्ट होगी।

जुब्बडहट्टी हवाई अड्डे के निकट माउंटेन टाउन का मास्टर प्लान दो सप्ताह में होगा तैयारः सुधीर शर्मा

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शिमला के निकट जुब्बडहट्टी हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित माउंटेन टाउन परियोजना के निष्पादन को लेकर हिमुड़ा व सिंगापुर कॉप्रेशन एंटरप्राईज के बीच एक बैठक आयोजित की गई। इस निष्पादन एजेंसी का चयन सिंगापुर सरकार द्वारा किया गया है।

बैठक में परियोजना के शीघ्र निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा प्रस्तावित टाउन की योजना को अन्तिम रूप दिया गया।

शर्मा ने बताया कि परियोजना के लिए 'स्पेशल परपज व्हीकल' का गठन एक माह के भीतर किया जाएगा, जिसके पांच सदस्यीय बोर्ड होंगे, जिनमें में एक सदस्य हिमुडा का तथा चार सदस्य सिंगापुर कॉप्रेशन एंटरप्राईज के होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के मास्टर प्लान को दो सप्ताह के भीतर अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तथा हिमाचल प्रदेश व सिंगापुर सरकार के बीच परियोजना को लेकर एक माह के भीतर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे।

हिमुड़ा के प्रमुख अभियन्ता श्री उमेश शर्मा, मुख्य लेखा अधिकार चन्द्र शेखर सेवाल, वरिष्ठ वास्तुकार, हिमुड़ा के इंजीनियर व सिंगापुर कॉप्रेशन एंटरप्राईज के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

अगर धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया जाता है, तो धन बोझ बन जाता है, और उस बोझ तले व्यक्ति दबता चला जाता है .....'स्वामी विवेकानंद'

सम्पादकीय

किसान की उपेक्षा क्यों

भारत कृषि प्रधान देश है। इसके करीब 70 % लोग आज भी गांवों में रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। यह आज भी हकीकत है और इसी के साथ जुड़ी एक बड़ी हकीकत है कि खाने की हर चीज खेत से ही निकलती है। इसका कोई विकल्प किसी मशीन से अब तक तैयार नहीं हुआ है। फिर जिस क्षेत्र पर 70% आबादी आश्रित हो उससे बड़ा रोजगार का कोई और साधन हो नही सकता लेकिन क्या शासन और प्रशासन इसे स्वीकार करने के लिये तैयार है। यदि सरकार इस सीधी सच्चाई को स्वीकार कर ले तो बहुत सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज कृषि का स्थान सबसे अन्त में धकेल दिया गया है। एक समय यह माना जाता था कि " **उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी.....।**" लेकिन आज इस धारणा को एकदम उल्ट दिया गया है और इस उल्टने का ही परिणाम है कि आज देश का किसान आन्दोलन के रास्ते पर निकलने को मजबूर हो गया है। क्योंकि दूसरो का अन्नदाता आज स्वयं आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया है। आज आन्दोलन के दौरान पुलिस की गोली से होने वाली मौतें भी उसके आन्दोलन के संकल्प को हिला नही पा रही है।

इस किसान आन्दोलन को समझने के लिये थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। शासन का खर्च लगान से चलता है और इस लगान का मुख्य स्त्रोत किसान और उसका खेत होता है यह एक स्वीकृत सच्चाई है। आज इस लगान का पर्याय टैक्स है। एक समय था जब यह लगान सीधे पैदा हुए अन्न के रूप में ही उगाहया जाता था। लेकिन अंग्रेज शासन के दौरान यह लगान अन्न से हटकर सीधे नकद के रूप मे बसूला जाने लगा । इस नकद बसूली के कारण किसान को साहूकार से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी और जब इस नकद कर्ज को वह समय पर नही लौटा सका तो उसके खेत निलाम होने लग गये। 1861 के आसपास किसान और साहूकार के रिश्ते इस मोड़ पर आ गये कि किसानों ने साहूकारों का घेराव करना शुरू कर दिया। साहूकारों के घर में घुसकर उनसे कर्ज के कागजात छीन कर उनको जला दिया जाने लगा। इस स्थिति को देख कर अंग्रेज शासन साहूकार की सहायता के लिये आगे आ गये और उस जमाने में करीब तीन हजार किसानों की गिरफ्तारी हुई थी। किसानों की गरीबी पर बासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिवा फुले ने सबसे पहले बड़े विस्तार से चर्चाएं उठायी थी और इन्हीं चर्चाओं के परिणामस्वरूप आजादी के बाद सहकारिता और किसान आन्दोलन के लिये वैचारिक धरातल तैयार हुआ।

1980 – 81 में पूना के निंपाणी में तम्बाकू उत्पादक किसानों का आन्दोलन किसान आन्दोलनों के इतिहास में पहला सफल आन्दोलन रहा है जब मार्च 81 में चालीस हजार किसानों ने अपनी बैलगाड़ीयां लेकर पूना – बंगलौर राजमार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया था। 23 दिन चले इस आन्दोलन पर पुलिस ने आंसू गैस और गोली चलाई जिसके कारण 12 किसान इसमें शहीद हुए लेकिन इस आन्दोलन से देश के हर हिस्से में बैठा किसान अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हुआ और उसने अपनी उपज के उचित मूल्य की मांग समाज और सरकार के सामने रखी। 1981 के पूना के इस आन्दोलन का ही प्रभाव है उसके बाद पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भी अपने उत्पाद के उचित मूल्य की मांग करने लगे है। आज किसान आन्दोलन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राज्यस्थान से निकलकर पंजाब हरियाणा में अपनी दस्तक देने वाला है। किसान गरीब है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है क्योंकि उसे बाजार में उसकी उपज का उचित मूल्य नही मिल पा रहा है। इसके लिये किसान इस कर्जे से मुक्ति के लिये कर्ज माफी और उसकी उपज के लिये मूल्य निर्धारण की मांग कर रहा है। आज उत्पादक किसान और उपभोक्ता के बीच मूल्य को लेकर इतना बड़ा अन्तर है जिसके कारण दोनों ही अपने – अपने स्थान पर हताश और पीड़ित हैं। उत्पादक किसान आत्महत्या के कगार पर है और उपभोक्ता बढ़ती कीमतों से पेरशान होकर उनका उपयोग – उपभोग छोड़ने को विवश है। लेकिन दोनों के बीच का जो अन्तराल है इसे समझने और पाटने में शासन और प्रशासन पूरी तरह ऑख बन्द करके बैठा है। आज कुछ राज्य सरकारों ने किसान का कर्जा माफ करने की घोषणाएं की है लेकिन इन घोषणाओं के साथ ही केन्द्र के वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की कर्ज माफी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को अपने संसधनों से उठानी होगी। केन्द्र इसमें कोई सहायता नही करेगा। लेकिन हर राज्य सरकार भारी भरकम कर्ज के बोझ तले है। यह कर्जभार जीडीपी के 3% की सीमा से कहीं अधिक हो चुका है। लेकिन इस कर्ज पर नजर दौडाई जाये तो यह कर्ज विभिन्न उद्योगों की स्थापना और फिर उनको राहत की शक्ल में दिये गये पैकेजो का परिणाम है। उद्योग पैकेजों के बाद इस कर्ज से समाज के कुछ वर्गो को सस्ता राशन , वृद्धावस्था, विधवा बेरोजागारी आदि के लिये दी जाने वाली पैन्शन दी जा रही है। लेकिन सरकारों के इस बढ़ते कर्ज से किसान को कुछ नही मिला है यह स्पष्ट है। फिर जिस अनुपात में उद्योगों को पैकेज दिये जा रहे हैं उस अनुपात में यह उद्योग रोजगार के अवसर पैदा नही कर पाये हैं।

इस परिदृश्य में आज किसान और उद्योग आमने – सामने खड़े होने के कगार पर पहुंच गये हैं। कारखाने को कच्चा माल तो किसान के खेत से जा रहा है या उसके खेत के नीचे दबे खनिज से। लेकिन सरकार इन उद्योगपतियों का तो कई लाख करोड़ का कर्ज माफ करने को तैयार बैठी है लेकिन किसान के लिये नही। आज किसान सरकारों की इस नीयत और नीति को समझ चुका है इसलिये उसे अब और अधिक नजर अन्दाज कर पाना संभव नही होगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तीन वर्षों में नई सफलताएं अर्जित की

हमारी पृथ्वी कैसी है? यह अपने में किन चीजों को समाहित किये हुए है? पृथ्वी का भविष्य क्या होगा और मनुष्य को पृथ्वी के तत्वों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मानव सभ्यता की उच्च आकांक्षाओं के कारण हमारी पृथ्वी में बहुत भारी उथल – पुथल चल रही है। सबसे बढ़कर जलवायु परितर्वन का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा है। प्रकृति की अनिश्चितताओं को जानना हमारे लिए एक कठिन चुनौती है। मानवता के इन कठिन मामलों को समझने के लिए भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) भारत और विदेशों में वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न है और पिछले तीन वर्षों में इसने विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं।

* रत्नदीप बनर्जी

पृथ्वी सर्वोपरि

4000 मीटर की ऊंचाई पर बसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति में एक शोध केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र का नाम हिमांश है, जो हिमालय के ग्लेशियरों पर अध्ययन करता है। हिमाशं का शाब्दिक अर्थ है बर्फ का टुकड़ा। चन्द्रा नदी के 130 किलोमीटर की दूरी में पांच स्थानों पर जलस्तर रिकॉर्ड करने तथा हाइड्रोलोजिक संतुलन मापने के लिए केन्द्र स्थापित किये गये हैं। क्षेत्रीय लेजर स्केनर और मानवरहित हवाई वाहनों से ग्लेशियर की गति तथा बर्फ आच्छादन में आए बदलाव का सर्वे किया जा सकेगा और इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त द्रव्यमान संतुलन जानने के लिए छह ग्लेशियरों पर 150 क्षरण खम्भे स्थापित किये गये हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होगी। भूमि प्रतिच्छेदी रडार द्रव्यमान और आयतन की गणना कर रहा है, जो द्रव्यमान संतुलन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। हिमांश स्वचालित मौसम केन्द्र, स्टीम ड्रील, जीपीएस, धारा को मापने के लिए यंत्र के अलावा अन्य आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है।

भारत की पहली बर्फ वेधशाला (मूरर्ड अर्ब्जवेट्री) आर्कटिक में पानी के 180 मीटर नीचे स्थापित की गई है। यह वेधशाला सर्दियों के मौसम में भी पृथ्वी की सतह के नीचे के आंकड़े एकत्र कर सकती है, जब ऊपरी सतह पर बर्फ जम गई हो। लम्बे समय तक आंकड़ों के संग्रह से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बदलाव तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को जानने में सहायता मिलेगी।

वैज्ञानिक और आम आदमी सभी यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है? इसकी झलक कैसी है? पिछले वर्ष भारत के बोरहोल भूविज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला ने महाराष्ट्र के कोयना में पृथ्वी के क्रर्स्ट का वैज्ञानिक गहरा प्रतिच्छेदन प्रारंभ किया और इसका पायलट बोरहोल 2662 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इस अध्ययन से पृथ्वी के अंदर विशाल जल भंडार भूकंप को किस तरह प्रभावित करते हैं, को जानने में मदद मिलेगी। इससे भूकंप के पूर्वानुमान का म डल विकसित करने में भी सहायता मिलेगी।

पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय महासागर ड्रिलिंग कार्यक्रम के तहत अरब सागर में गहरे समुद्र की ड्रिलिंग की गई। यह पर्वत निर्माण, मौसम, अपरदन और जलवायु के विकास के अध्ययन के उद्देश्य से किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत और सेशल्स के बीच महाद्वीपीय विखंडन और इसका दक्षिण के पठार के ज्वालामुखीय आवरण से संबंध अध्ययन के विषय थे।

धरुवीय अनुसंधान में भारत के वैज्ञानिक योगदान और प्रयासों को मान्यता देने के तहत आर्कटिक परिषद में देश को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत का अंटार्कर्टिक वैज्ञानिक अभियान के 35वें और 36वें संस्करण में विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए थे। ये संगठन ऊपरी वायुमंडल, खगोल भौतिकी, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान, ग्लेसिओलॉजी,

भूविज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पिछले वर्ष जलवायु परितर्वन और ग्लेशियर अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था। भारत ने तीसरा स्थायी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है, जिसका नाम भारती है। इसने ग्लेशियर, वायुमंडल, जलवायु और ध्रुवीय जीवविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है।

2015 में ध्रुवीय क्षेत्र में रिमोर्ट से संचालित वाहन का शुभारंभ किया गया, जो अंटार्कटिक में जलस्तर के 100 मीटर नीचे है। यह एक तकनीकी उपकरण है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जलस्तर के 500 मीटर नीचे तक के क्षेत्रों में अन्वेषण कर सकता है। 2016 में इसे अंडमान, प्रवाल द्वीपों में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था और इस वाहन ने प्रवाल जैव विविधता की उच्चस्तरीय विजुअल प्रदान किये थे।

भारत, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महासागर ऊर्जा प्रणाली (आईईए – ओई एस) का सदस्य बना। इसके साथ ही भारत को पूरे विश्व में तकनीकी और अनुसंधान दलों के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिली। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ 15 वर्षों का समझौता किया है। इससे भारत को हिंद महासागर में बहु – धात्विक सल्फाइड (पीएमएस) के अन्वेषण में मदद मिलेगी। आईएसए का गठन महासागर के नियमों के समझौते (कन्वेंशन ऑन लॉ आफ द सी) के अंतर्गत हुआ है, जिसका सदस्य भारत भी है।

पृथ्वी विज्ञान आम लोगों को सलाह देता है, जैसे मौसम, चक्रवात और मानूसन की भविष्वाणी। इससे न सिर्फ कृषि, बल्कि जल संसाधन, विद्युत उत्पादन, परिवहन और भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्याधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

भारत में मछुआरे अपने अनुमान पर भरोसा करते रहे हैं, जिससे वे मछलियों की कम मात्रा प्राप्त कर पाते हैं। राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) मछुआरों को प्रति दिन संभावित मत्स्य क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराता है, ताकि वे उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें, जहां मछलियां बहुतायद में हैं। विभिन्न सैटलाइट के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिशानिर्देश युक्त नक्शे बनाए जाते हैं। इन दिशा निर्देश युक्त नक्शों में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सीमा रेखा के संबंध में जानकारी होती है, ताकि मछुआरे इसे और समुद्र की सतह पर चलने वाली धाराओं से दूर रह सकें।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश के 608 जिलों में स्थित 130 कृषि – मौसम – जोन के 21 मिलियन किसानों को क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि व मौसम संबंधी सुझाव प्रदान कर रहा है।

विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने पुणे स्थित भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के जलवायु केन्द्र को दक्षिण एशिया के देशों को क्षेत्रीय जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय जलवायु केन्द्र के रूप में मान्यता दी है। भारतीय मौसम संस्थान, पुणे के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी प्रणाली का एक म डल निर्मित किया है, जिसे आगामी छठे आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन आकलन प्रक्रिया में भारत के योगदान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस म डल का क्षेत्रीय जलवायु परितर्वन स्थितियों के अध्ययन के लिए पुन: उपयोग किया जा सकेगा। इसकी क्षमता 25 किलोमीटर तक है और यह जलवायु प्रभाव के आकलन का अध्ययन करने में सक्षम है।

सरकार के खर्च पर जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल होती हैं, वो आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। विज्ञान को सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधानों का लक्ष्य आम लोगों को सुविधा व लाभ पहुंचाना होना चाहिए।

–पसूका–

गंगा स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय मिशन की चुनौतियां

के.एन.पाठक

गंगा की स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत से पहले जो देश की सबसे सम्मानित और राष्ट्रीय नदी गंगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही थी। गंगा के अस्तित्व पर यह संकट बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से पैदा होनें वाले सीवेज, व्यापारिक प्रदूषण व अन्य प्रदूषणों के कारण हुआ हैं। गंगा पाँच राज्यों– उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल–से होकर बहती है और कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का एक चौथाई है। देश की 46 प्रतिशत आबादी गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में निवास करती है। यह पाँच राज्यों के 66 जिलों में फैले 118 शहरों तथा 1657 ग्राम पंचायतों से होकर बहती है।

गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत जून 2014 में की गई। इस मिशन को उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धा समूहों (एसपीएमजी) सहायता प्रदान करते हैं। 'नमामि गंगे योजना' के अन्तर्गत सीवर और प्रदूषण प्रबन्धन, नए एसटीपी का निर्माण तथा पुराने एसटीपी का पुनर्वास, ग्राम पंचायतों की पूर्ण स्वच्छ्ता, आदर्श श्मशान घाट/धोबी घाट का निर्माण, जीआईएस स्तर पर निर्णय लेने की प्रणाली का विकास तथा निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी केन्द्र की स्थापना जो वास्तविक समय पर चेतावनी और पूर्वानुमान प्रदान कर सके जैसी प्रमुख गतिविधियां हैं। लंबी अवधि के संरक्षण और पुनर्जीवन तथा ओ एण्ड एम के अन्तर्गत दस वर्षो के लिए सम्पत्तियों का निर्माण के लिए शत प्रतिशत धन राशि का प्रावधान किया गया है। जैव विविधता, संरक्षण, नदी के प्रवाह, नदी के दोनों किनारो पर औषधीय व स्थानीय पौधों का वनीकरण तथा जलीय जीवों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

नमामि गंगे योजना के पहले तीन वर्षो में (2014–15 से 2016–17) 3673 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च हुई है। चालू वित्त वर्ष (2017–18) में 2300 करोड़ रुपये की धनराशि बजट में आवन्टित की गई है। परन्तु यह देखा गया है कि धनराशि के उपयोग की गति संतोषजनक न है। निविदा में विलम्ब, पुनर्निविदा, जमीन की अनुपलब्धता, कानूनी मामले, प्राकृतिक आपदाएं, सड़क काटने की स्वीकृति में देरी, स्थानीय त्यौहार, अधिक कोष की आवश्यकता तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अनुशंसा में देरी आदि योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति के प्रमुख कारण हैं। आशा है कि संबंधित राज्य के साथ राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन की निरन्तर निगरानी बैठक से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जमीन उपलब्धता तथा निविदा द्वारा योजना की शुरूआत जैसी बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।

भारत के गजट द्वारा 7 अक्टूबर 2016, को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आने वाले गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरणों को तेज गति से नीति निर्माण व कार्यान्वयन तथा एक नए संस्थागत संरचना निर्माण का प्रावधान है। यह प्रावधान राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन को अपने कार्यो को स्वतन्त्र रूप से तथा जवाबदेही लेकर पूर्ण करने की शक्ति देता है। इस प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र पाँच राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा गंगा व उसकी सहायक नदियों तक विस्तृत है।

प्राधिकरण के लिए चिन्हित किये गए प्रमुख सिद्धान्त है:–

जल प्रवाह की निरन्तरता को बनाए रखना,

जमीन के ऊपर का प्रवाह तथा जमीन के अन्दर का पानी (भूमिगत जल) के बीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध का प्रबन्धान और पुनर्सथापना,

सम्पत्ति और जल की गुणवत्ता का समयबद्ध रख–रखाव और पुनर्स्थापना,

जल ग्रहण क्षेत्र में लुप्त हो चुके पेड़ पौधों का पुनर्जीवन और प्रबन्धन,

गंगा बेसिन में जलीय जीव और तटीय जैव विविधता का पुनर्जीवन और संरक्षण,

गंगा के किनारों तथा इसके बाढ क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबन्ध ताकि प्रदूषण के स्रोत कम किया जा सके और भूमिगत जल की फिर से पूर्ति की जा सके, नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा उद्योग निकायों के सहयोग से प्रमुख शहरों में गंगा नदी के तल की सफाई का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। ग्रामीण स्वच्छता के तहत राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को शौचालय निर्माण के लिए 263 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये है। अब तक 11 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है। श्मशान घाटों के निर्माण व आधुनिकीकरण के लिए 20 से 25 शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से प्रतिवर्ष 100 श्मशान घाटों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

केदारनाथ, हरिद्वार, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और पटना में नदी के किनारों/घाटों का विकास कार्य तथा वर्तमान के घाटों की मरम्मत और आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अत्यधिक प्रदूषित करने वाले 764 में से 508 शराब, लुग्दी व कागज, चमड़ा उद्योग, वस्त्र तथा चीनी के कारखानों के लिए वास्तविक समय पर जानकारी देने वाले प्रदूषण निगरानी केन्द्रों की स्थापना की गई है। यह प्रदूषण प्रबन्धन कार्य, मध्यम अवधि योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया गया है। शराब के कारखानों के द्वारा शून्य द्रव निर्वहन के लिए कार्य योजना 2016 के अन्तिम तिमाही से लागू की गई है। केन्द्रीय नियन्त्रण प्रदूषण बोर्ड से सतर्कता विभाग द्वारा बारीकी से निर्देशो के अनुपालन की निगरानी की जा रही है।

भारत के वन्य जीव संस्थान के सहयोग से जैव विविधता संरक्षण को लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत स्वर्ण महशीर, डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुए और ओटर आदि का संरक्षण शामिल है। वनीकरण कार्यक्रम के तहत 30,000 हैक्टेयर भूमि का लक्ष्य रखा गया है। जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 57 निगरानी केन्द्रों के अलावा 113 वास्तविक समय निगरानी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जो कुछ निश्चित जगहों पर प्रदर्शन बोर्डो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगें। पोस्टर, ब्रोशर, पर्चे, होर्डिंग आदि जैसे संसाधन सामग्रियों को हितधारकों के बीच प्रसारित/प्रदर्शित किया गया है।

पैदल यात्रा, स्वच्छता अभियान, बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, श्रमदान, टॉक–शो और संवाद आदि के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। एक नमामि गंगे गीत जारी किया गया है इसे डिजीटल मीडिया और अन्य कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दृश्य–श्रव्य के माध्यम से भी जागरुकता फैलाई जा रही है। फेसबुक, ट्वीटर और यू टड्बू जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों से अद्यतन जानकारी मुहैया कराई जा रही है। जन जागरूकता अभियान, फोटो प्रदर्शनियां, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मंडप/स्टालों को लगाने की भी शुरुआत की गई है। गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी के लिए 'भुवन–गंग' वेब ऐप और मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया गया है।

गंगा पुनर्जीवन चुनौती की प्रकृति को देखते हुए भारत सरकार के सात मंत्रालय जून 2014 से एक साथ मिलकर कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन और भारत सरकार के 11 मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए है ताकि गंगा नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण के क्रियाकलापों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) के विभाग राष्ट्रीय रिमोर्ट सेंसिंग केन्द्र के साथ भी समझौता किया गया है।

गंगा नदी में प्रदूषण में कमी लाने तथा स्वच्छता अभियान के लिए नीति बनाने वाले उच्च स्तरीय प्राधिकरणों ने बारीकी से निगरानी करने, अपशिष्ट का उत्पादन कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट निष्पादन और लोगों में बिजली के श्मशान घाट की स्वीकार्यता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। लोगो को निगरानी की रिपोर्टो से अवगत कराने की अनुशंसा की गई है।

हाल ही में लिए गए कुछ निर्णय यह इंगित करते है कि प्रदूषण नियन्त्रण तथा नदी के प्रवाह को निरन्तरता प्रदान करने की योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है। राज्य गंगा समितियां तथा जिला गंगा समितियां गठित की गई है ताकि गंगा के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तथा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। –पसूका–

समेकित विकास की दहलीज पर वस्त्र मंत्रालय

*** जी. श्रीनिवासन**

मोदी सरकार का महत्वपूर्ण मिशन, 'मेक इन इंडिया' इस मूल अवधारणा को निर्दिष्ट करता है कि यह घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देगा तथा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसलिए हल्के विनिर्माण उपक्षेत्रों जैसे चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग को अधिक प्रमुखता दी गई है, ताकि उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी हो सके।

वैश्विक व्यापार संधि के रूप में वस्त्र पर प्रतिबंधात्मक बहु–फाइबर व्यवस्था (एमएफए)1972 से लागू थी, जिसकी समाप्ति 2004 में हुई। यह संधि विकासशील देशों को विकसित देशों को सूत (यार्न), कपड़ा और तैयार वस्त्र निर्यात करने में कोटा के माध्यम से प्रतिबंधित करती थी। इस संधि की समाप्ति से भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतियोगी निर्यातकों को बड़े स्तर पर सुअवसर प्राप्त हुआ। इस कोटा व्यवस्था को समाप्त हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन भारत इस सुअवसर का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है, जबकि अन्य देश प्रतिस्पर्धी कीमत और समयबद्ध माल–अदायगी से लाभ कमा रहे हैं।

हालांकि पिछले कुछ वर्षो से स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो आशान्वित करता है। वस्त्र मंत्रालय विभिन्न सुविधाओं को जोड़ने में व्यस्त है, ताकि वस्त्र उद्योग को घरेलू खपत और निर्यात में बढ़ोतरी मिल सके।

वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन लोग कार्यरत हैं और लगभग इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योग में मूल्य संवर्धन प्रक्रिया से जुड़े हैं। इस क्षेत्र में भारत तुलनात्मक रूप से अनुकूल तथा फायदेमंद स्थिति में है। पारम्परिक रूप से भारत वस्त्र निर्यात में विश्व बाजार, विशेषकर अमरीका और 27 सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। सूत निर्यातक के रूप में भारत को चीन और बांग्लादेश जैसे अपने प्रतियोगी देशों से इस अर्थ में श्रेष्ठता प्राप्त है कि वह वस्त्र तैयार होने से पहले की स्थिति में मूल्यवर्धन प्रक्रिया को मजबूती प्रदान कर सकता है।

घरेलू खपत और निर्यात में वृद्ध के लिए वस्त्र मंत्रालय ने जून 2016 में वस्त्र उद्योग को 6000 करोड़ रुपये का एक प्रोत्साहन पैकेज दिया। इसके साथ ही दिसंबर, 2016 में तैयार वस्त्रों के लिए नई नीतियां बनाई गई। पैकेज का निर्माण रोजगार के अवसर पैदा करने, निवेश बढ़ाने तथा वस्त्र निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इन नीतियों में श्रम कानून, कार्यावधि, वेतन और भत्तों में सुधार शामिल थे। इसके अंतर्गत नियत अवधि तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई, ताकि अल्पकालिक श्रमिक भी पूर्णकालिक कामगारों के समान सुविधा प्राप्त करें और वे वस्त्र उद्योग में अपने योगदान देने से भयभीत न हों।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (एटीयूएफएस) के अंतर्गत उत्पादन और रोजगार योजना को वस्त्र उद्योग की इकाइयों (एसपीईएलएसजीयू) से जोड़ दिया गया। इस योजना को 10 जनवरी, 2017 से तैयार वस्त्रों के लिए भी लागू कर दिया गया। संशोधित टीयूएफ के तहत वस्त्र और तैयार वस्त्रों की इकाइयों के लिए सब्सिडी 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिली। ऊपरी सीमा को भी बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सब्सिडी उत्पादन केंद्रित है और इसका भुगतान वैसी स्थिति में ही किया जाएगा, जब तीन वर्षो के दौरान रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये गए हों। इसके साथ ही, आयकर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए के तहत 240 दिनों के प्रावधान को घटाकर वस्त्र उद्योग के लिए 150 दिन कर दिया गया। मौसमी प्रकृति को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुआ है।

निर्यातकों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य लेवी टैक्स छूट योजना (आरओएसएल) को 12 अगस्त, 2016 से लागू किया गया। यह योजना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू की गई कि वैश्विक नियमों के मुताबिक करों का निर्यात नहीं किया जा सकता।

वस्त्र मंत्रालय की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं– पावरलूम कलस्टर निर्माण के लिए योजनाएं, रेशम उद्योग के विकास के लिए समेकित योजना (आईएसडी एसआई), व्यापक हैंडलूम कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस), राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय वस्त्र विकास योजना (एनईआर टीपीएस)। इसके अतिरिक्त, कुछ वर्ष पूर्व समेकित वस्त्र पार्क (एसआईटीपीएस) का शुभारंभ किया गया, जो तेजी से प्रगति कर रहा है। एसआईटीपी का प्राथमिक उद्देश्य है विकास संभावित केन्द्रों पर विश्वस्तरीय अवसंरचना को मूल्य संवर्धन प्रणाली से एकीकृत करना। इससे वस्त्र उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकेगा। इसका लक्ष्य केन्द्र आधारित अवसंरचना की बाधा को समाप्त करना, अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था करना तथा रोजगार सृजन करना है। इस योजना में उद्योग जगत की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार की भूमिका कोष की व्यवस्था करने तथा सुविधा प्रदान करने तक सीमित है। राज्य सरकारों को भी इन पार्कों के चयन और मंजूरी देने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में वस्त्र पार्क के निर्माण के लिए 152 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

उत्पादन–परिणाम की कार्य योजना के तहत वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग को गति प्रदान करने के लिए 3094 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है ताकि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और लाखों लोगों को रोजगार मिल सके।

निष्कर्षत:नई नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग को अपने सभी शाखाओं–सूती वस्त्र, हैंडलूम, पावरलूम, हस्तकला, रेशम और तकनीक आधारित वस्त्र के साथ समेकित विकास करने में मदद मिलेगी। –पसूका–

नगर निगम पर कब्जा करेगी निर्दलीय के सहारे भाजपा

शिमला/शैल। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व आगामी चुनाव में भाजपा से संभावित सीएम के दावेदार मोदी सरकार के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अंदरूनी जंग के बीच शिमला नगर निगम पर कब्जा करने के लिए निर्दलीय का सहारा लेना पड़ रहा है।

नगर निगम में 34 सीटों में से

भाजपा ने 17 वार्डो में जीत हासिल की हैं जबकि कांग्रेस के 12 ही पार्षद जीत सके। वामपंथी एक ही सीट जीत पाए। पिछले बार निगम में वामपंथियों के दो महिला पार्षद थी जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष हुए थे। ऐसे में इन पदों पर भी वामपंथी ही जीते थे। इन चुनावों में चार निर्दलियों ने भी जीत हासिल की हैं। इनमें से एक निर्दलीय भाजपा से हैं बाकी के तीन कांग्रेस के हैं। वामपंथी पार्टी माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद ने दावा किया है कि छह से ज्यादा वार्डो में वामपंथी दूसरे नंबर पर रहे हैं।

उधर,भाजपा के सूत्र बताते है कि भाजपा के दोनों खेमे मिलकर काम करते तो भाजपा के 25 से ज्यादा पार्षद होते। कांग्रेस पार्टी व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के लिए काम ही नहीं किया। सीएम आखिर में प्रचार में कूदे। ऐसे में भाजपा के पास निगम चुनावों पर अपनी आंधी चलाने का मौका था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसे बागी का सहारा लेना पड़ रहा है।

बहरहाल, अब निगम पर भाजपा कब्जा करने जा रही है। भाजपा नगर निगम पर 31 सालों के बाद कब्जा करेगी। पार्टी को इसी बात का मलाल था कि जनता ने वामपंथियों तक को सता दे दी लेकिन भाजपाइयों को मौका नहीं दिया। पार्टी अध्यक्ष सतपाल सती और निगम चुनावों के प्रभारी राजीव बिंदल ने अपना दर्द मीडिया से साझा भी किया था। बिंदल चुनावों के कारगर रणनीतिकार माने जाते रहे हैं। जब प्रचार के दौरान उन्हें ये लगा की पार्टी को रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो वो धूमल को मैदान में उतार ले आए और जिन वार्डो में धूमल के करीबी खड़े थे वहां प्रचार करवाया। बेनमोर से किमी सूद, रुल्दू भटटा से संजीव ठाकुर, कृष्णा नगर से बिटटू पाना, बालूगंज से किरण बाबा जैसे ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें धूमल के बेहद करीबी माना जाता है। इनमें से कुछ अनुराग ठाकुर की एचपीसीए से भी जुड़े हैं।

प्रचार के दौरान ही ये चल पड़ा था कि नड्डा खेमा और धूमल खेमा एक दूसरे के लाडलों को चित करने के लिए भितरघात करेगा। लोअर बाजार व रामबाजार में तो ये भितरघात हुआ भी व यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए। जाखू में भी ऐसा ही हुआ। यहां भी एचपीसीए के उपाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर की बीवी खड़ी थी वो हार गई। चूंकि धूमल को प्रचार में ज्यादा दिन उतरने ही नहीं दिया तो काम करने का मौका नहीं मिला।

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि नगर निगम पार्षद चुनाव के सभी 34 वार्डो के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मतगणना शनिवार सुबह 9 बजे से बचत भवन शिमला और डीसी कोर्ट रूम में की गई।

उन्होंने बताया कि भराड़ी वार्ड से तनुजा चौधरी, रूलदुभट्ठा से संजीव ठाकुर, कैथू से सुनीलधर, अनाडेल से कुसुम सदरेट, समरहिल से शैली शर्मा, टुटू से विवेक शर्मा, मज्याट से दिवाकर देव शर्मा, बालुगंज से किरण बावा, कच्ची घाटी से संजय परमार, टूटीकंडी से आनंद कौशल, नाभा से सिम्मी नंदा, फागली से जगजीत सिंह बग्गा, कृष्णानगर से बिटू कुमार, राम बाजार से सुषमा कुठियाला, लोअर बाजार से इंद्रजीत सिंह, जाखू से अर्चना धवन, बैनमोर से किमी सूद, इंजनघर से आरती चौहान, संजौली चौक से सत्या कौंडल, अप्पर ढली से कमलेश मेहता, लोअर ढली से शलैन्द्र चौहान, शान्ति बिहार से शारदा चौहान, भट्ठाकुफर से रीता ठाकुर, सांगटी से मीरा शर्मा, मल्याणा से कुलदीप ठाकुर, पंथाघाटी से राकेश कुमार शर्मा, कुसुम्पटी से राकेश चौहान, छोटा शिमला से विदूषी शर्मा, विकास नगर से रचना, कंगनाधार से रेणु चौहान, पटयोग से आशा शर्मा, न्यू शिमला से कुसुमलता, खलीनी से पूर्ण मल, कनलोग से बृज सूद को निर्वाचित घोषित किया गया है।

वार्ड न. 22 कि उम्मीदवार शारदा चौहान ने सबसे कम 5 वोटों से जीत हासिल की जबकि वार्ड न. 33 के उम्मीदवार पूर्ण मल ने सबसे अधिक 541 वोटों से जीत हासिल की। नगर निगम चुनाव में इस बार 34 वार्डो में None of the above पर 363 वोट डला है। जिसमें सबसे अधिक कृष्णा नगर में 28 वोट NOTA को डले है जबकि यहां से सबसे अधिक 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इसके इलावा समरहिल से 25, जाखू से 22 रूलदूभट्टा और खलिणी से 20-20 वोट NOTA को डले हैं।

नतीजों का वार्ड वाईज़ विवरण इस प्रकार है

वार्ड न. नाम उम्मीदवार नाम मत

1 भराड़ी
1. तनूजा चौधरी 477
2. मीना चौहान 467
3. रूचि सूद 395
4. नोटा 11

2 रूलदूभट्ठा
1. प्रकाश सिंह रावत 302
2. मनप्रीत सिंह 701
3. संजीव ठाकुर 1193
4. नोटा 20

3 कैथू
1. कांता सुयाल 655
2. देवेन्द्र चौहान 469
3. सुनील धर 681
4. नोटा 10

4 अनाडेल
1. कुसुम सदरेट 942
2. जैनी प्रेम 643
3. शिखा 144
4. नोटा 14

5 समरहिल
1. अंजना ठाकुर 299
2. शैली शर्मा 871
3. सुषमा देवी 622
4. नोटा 25

6 टुटू
1. कमलेश कुमार 392
2. विजेन्द्र मेहरा 418
3. विवेक शर्मा 515
4. संगीत कुमार 325
5. नोटा 5

7 मज्याट
1. कैलाश वर्मा 109
2.दिवाकर देव शर्मा 255
3. धर्म सिंह ठाकुर 90
4.राजीव कुमार 82
5.शिवराम भारद्वाज 202
6. नोटा 7

8 बालूगंज
1. इन्दू ठाकुर 434
2. किरण बावा 846
3. रेणु 53
4. नोटा 4

9 कच्ची घाटी
1. मनोज कुमार 454
2. सावित्री देवी 55
3. सुरेश ठाकुर 37
4. संजय परमार 726
5.संजीव कुमार शर्मा 281
6. नोटा 7

10 टूटीकंडी
1. अभिषेक बैनर्जी 170
2.आनन्द कौशल 951
3.जय चंद 624
4. नोटा 17

11 नाभा
1. सिम्मी नंदा 872
2. हिमा देवी 851
3. नोटा 14

12 फागली
1. राकेश कुमार 65
2. रूप चंद 515
3. कुलदीप सिंह 140
4.जगजीत सिंह बग्गा 941
5. नोटा 17

13 कृष्णानगर
1. कृष्णा कुमारी 34
2. बिटू कुमार 754
3. नरेश कुमार 459
4. बिट्टू 32
5. नवीता 70
6. विक्की 324
7. विजय कुमार 303
8. विनोद कुमार 54
9. सोनिया 295
10. नोटा 28

14. राम बाजार
1. किशोरी लाल ढटवालिया 461
2.दीपक शर्मा श्रीधर 541
3. सुषमा कुठीयाला 615
4. संजीव शर्मा 411
5. नोटा 17

15 लोअर बाजार
1. इन्द्रजीत सिंह 665
2. उत्तम सिंह 227
3. नवीन कुमार 479
4. नोटा 6

16 जाखू
1. अर्चना धवन 636
2. अंजना ठाकुर 620
3. नोटा 22

17 बैनमोर
1. किमी सूद 707
2. गीता देवी 141
3. महिमा चौहान 207
4. नोटा 1

18 इंजन घर
1.अनिता ठाकुर 651
2. आरती चौहान 673
3. बिन्दू जोशी 226
4. नोटा 10

19 संजौली चौक
1. पवन कुमार 10
2. बलजीत 930
3. सत्या कौंडल 1052
4. नोटा 14

20 अप्पर ढली
1. ईश्वरा हेटा 186
2. कमलेश मेहता 515
3. नोटा 3

21 लोअर ढली
1. गोपाल शर्मा 765
2. शैलेन्द्र चौहान 984
3. नोटा 9

22 शान्ति बिहार
1. गीता शर्मा 303
2. तनुजा थाप्टा 243
3. प्रतिभा बाली 486
4. रीना वर्मा 525
5. शशी बहल 181
6. शारदा चौहान 530
7. नोटा 1

23 भट्टाकुफर
1. देव कली नेगी 28
2. रीता ठाकुर 732
3. शीतल शर्मा 271
4. नोटा 4

24 सांगटी
1. निशा वर्मा 551
2. मीरा शर्मा 822
3. रंजना वर्मा 464
4. नोटा 3

25 मल्याणा
1. ईश्वर शर्मा 155
2. कुलदीप ठाकुर 377
3.दलीप सिंह सिंगटा 353
4. रोशन शर्मा 74
5. विरेन्द्र ठाकुर 185
4. नोटा 2

26 पंथाघाटी
1. धीरज राम 2
2. पुनीत धांटा 119
3. मनीष मेहता 133
4. मोहित ठाकुर 292
5.राकेश कुमार शर्मा 347
6. राजन ठाकुर 302
7. रूप राम चौहान 107
8.विद्या सागर नाम्टा 27
9. नोटा 4

27 कुसुम्पटी
1. अजय चौहान 9
2. अक्षय दिलैक 42
3. दौलतराम चौहान 327
4. मनीष ठाकुर 131
5. राकेश चौहान 477
6. राज कुमार शर्मा 132
7. राजीव शर्मा 241
8. विरेन्द्र कुमार 93
9. नोटा 5

28 छोटा शिमला
1. अनिता वर्मा 178
2. विदूषी शर्मा 712
3.शारदा देवी खन्ना 79
4. सीमा चौहान 605
5. नोटा 8

29 विकास नगर
1. मंजूला चौहान 434
2. रचना 651
3. रमा 144
4. सुमन 633
5. नोटा 15

30 कंगनाधार
1. मोनिका बांचटा 328
2. रेणू चौहान 380
3. शकुंतला शर्मा 224
4. नोटा 5

31 पटयोग
1. आशा शर्मा 608
2. महिमा ठाकुर 436
3. नोटा 14

32 न्यू शिमला
1. कुसुम लता 728
2. विजय परमार 545
3. नोटा 3

33 खलीनी
1. जीत राम पंवर 701
2. पूर्ण मल 1242
3. नोटा 20

34 कनलोग
1. आरती शर्मा 93
2. आशा सूद 269
3. पूनम पठानिया 353
4. बृज सूद 830
3. नोटा 18

फिल्मी स्टाईल में लाए गये गुप्त जगह रखे भाजपा पार्षद

शिमला/शैल। भाजपा और कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं व समर्थकों की आड़ में बाहुबल के प्रदर्शन के बीच सोमवार को तय शेडयूल के मुताबिक राजधानी में भाजपा, कांग्रेस, माकपा के अलावा निर्दलीयों ने पार्षद पद की शपथ ली लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं चुना जा सका। भाजपा ने कांगेस के इतिहास को दोहराते हुए बाहुबल का प्रदर्शन किया। ये सब भाजपा विधायक राजीव बिंदल का कौशल था।अब मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव कल मंगलवार 11 बजे होना है। ऐसे में दिलचस्प ये हो गया है कि क्या वीरभद्र सिंह व उनके बाहुबली बिंदल के घेरे को तोड़ पाते हैं या नहीं।

1998 में वीरभद्र सिंह भाजपा के शांता खेमे के विधायक रमेश ध्वाला को उठा ले गए थे व सरकार बना ली थी। तब ध्वाला निर्दलीय जीते थे। लेकिन 13 दिन बाद वो विश्वास मत हार गए थे। ध्वाला भाजपा में आ गए थे व पांच साल तक धूमल की अगुवाई में सरकार बनाई थी।

चूंकि नगर निगम के चुनाव में 34 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा को 17 ही सीटें मिली हैं। एक भाजपा का बागी जीता है।

चुनाव के बाद कहीं गुप्त स्थान पर रखे गए भाजपा पार्षदों को भाजपा विधायक राजीव बिंदल की अगुवाई में शपथ स्थल तक पूरी धमक के बीच दर्जन भर विधायकों की गाडियों में बिठाकर सीटीओ तक लाया गया। जैसे ही ये पार्षद सीटीओ में उतरे उन्हें समर्थकों की आड़ में भाजपा के बाहुबलियों की फौज ने घेर लिया और नारेबाजी करते हुए शपथ स्थल बचत भवन को ले गए।

इसी तरह कांग्रेस के पार्षद भी शपथ लेने पहुंचे। साढ़े तीन बजे के बाद बचत भवन में सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई व सवा चार बजे मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव करने का समय रखा गया। लेकिन कांग्रेस के सभी पार्षद व माकपा की पार्षद चले गए। वो वापस नहीं लौटे। अंदर केवल भाजपा के 17, एक निर्दलीय जो बाद में भाजपा में चला गया था, अंदर रहे हैं। इसके अलावा कच्ची घाटी से जीते कांग्रेस के बागी संजय परमार भी भाजपा के पार्षदों के साथ अंदर ही रहे। वो शपथ लेने भाजपा पार्षदों के साथ आए। इससे पहले भाजपा ने उन्हें कांग्रेस के खेमे से अपने खेमे में ला दिया। इस बावत क्या डील हुई हैं इसका पता बाद में चलेगा। दोपहर को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस का ये बागी भाजपा का हो गया है और 34 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा के 19 सदस्य हो गए हैं।

बचत भवन में शपथ के बाद जब कांग्रेस के पार्षद नहीं आए तो भाजपा विधायक सुरेश भारद्वाज ने दलीलें दी कि हाईकोर्ट को फैसला है व मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव आज ही होना हैं। इस पर डॉयरेक्टर अर्बन डवलपमेंट डी के गुप्ता ने फैसला दिया कि वो मंगलवार को 11 बजे मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करने का समय निर्धारित करते हैं। इस पर सुरेश भारद्वाज ने आपति जताई। तो डी के गुप्ता ने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब मंगलवार को मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। लेकिन सबसे बडी चुनौती भाजपा की है कि वो अपने 19 पार्षदों को कैसे सुरक्षित रखती हैं। अगर किसी ने बीच में से अगवा करने की शिकायत कर दी तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा अपने बागी संजय परमार समेत कुरुक्षेत्र ले गए थे। उन्हें दोपहर को चक्कर स्थित पार्टी कार्यालय लाया गया व वहां से विधायकों की गाडियों में बचत भवन तक पहुंचाया गया। जिस धमक के साथ भाजपा के नेता पार्षदों को बचत भवन तक लाए उसे देखकर कांग्रेस नेताओं के चेहरे उतर गए।

शपथ के दौरान बचत भवन के बाहर भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस के लोग नाहन से नगर परिषद का भाजपा अध्यक्ष पद का दावेदार उठा कर ले गई थी। ऐसे में उन्हें अंदेशा था कि कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी। इसलिए वो सतर्कता बरत रही हैं। बिंदल बचत भवन के बाहर बाहुबली युवाओं की टोली को रणनीति समझाते नजर आए। जब मीडिया के लोग फोटो खींचने लगे तो उन्हें इंकार किया जाने लगा। कुछ तो तेवर भी दिखाने के मुड़ में थे।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व कांग्रेस पार्टी की तरह ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और मोदी सरकार में मंत्री जगत प्रकाश नडडा के खेमे भितरघात करते हुए निगम में बहुमत हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेस के 12 पार्षद जीते तो भाजपा 17 पर सिमट गई। भाजपा ने जीतते ही पंथाघाटी से पार्टी के बागी को अपने कब्जे में ले लिया। धूमल व सती एक दम हरकत में आ गए। इनको कुरूक्षेत्र कुछ लोग चंडीगढ़ बताते हैं ले गए। इस बीच कांग्रेस अपने बागियों को संभाल पाते भाजपा की टीम ने कांग्रेस के बागी संजय परमार को भी अपने खेमे में पहुंचा दिया।

उधर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनका लाडला विक्रमादित्य कहते रहे कि निगम पर कांग्रेस का मेयर कब्जा करेगा। वीरभद्र सिंह भली भांति जानते है कि कांग्रेस के कुल 12 पार्षद जीत कर आए हैं। ऐसे में सवाल है कि वो कांग्रेस का मेयर बनाने का दावा किस ताकत पर कर रहे थे। हालांकि य आज भी कहा जाता रहा कि भाजपा के 6–7 पार्षद सरकार के संपर्क में हैं। व सही समय आने पर कांग्रेस अपना कार्ड चलेगी।

शपथ लेने के बाद कांग्रेस के सारे पार्षद हॉलीलॉज पहुंचे व आगे की रणनीति बनाई।

उधर, वामपंथी पार्टी माकपा ने एलान किया कि वो कल होने वाले मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव से दूरी बनाकर रखेंगी । पार्टी के राज्य सचिव ओंकार शाद ने साफ किया कि माकपा की पार्षद न तो भाजपा व न ही कांग्रेस का समर्थन करेगी। वो जनता के मसलों को उठाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया के भाजपा व कांग्रेस दोनों को ही बहुमत नहीं मिला हैं। ऐसे में दोनों खरीद फरोख्त करने पर आ गए हैं। माकपा इसकी निंदा करती हैं।

उधर, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस के सभी पार्षद कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से दोबारा मिलेंगे व वहां पर फैसला लिया जाएगा कि वो 11 बजे क्या करेगी।

NGT ने पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से काम छीना

शिमला/शैल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश देते हुए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया समेत नौ राज्यों के बोर्डो की अध्यक्षों से काम छीन लिया हैं। ग्रीन पैनल ने कहा है कि इन बोर्डो के अध्यक्षों की नियुक्ति एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं हुई हैं। ऐसे में आगामी आदेश तक इनसे काम छीन लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को रखी गई हैं।

एजेंसी के मुताबिक एनजीटी ने हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, उतराखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलांगना और महाराष्ट्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के अध्यक्षों से भी तुरंत प्रभाव से काम छीन लिया है।

ये आदेश वीरवार को एनजीटी की जस्टिस आर एस राठौर की पीठ ने जारी किए हैं। इस आदेश के आने के बाद हिमाचल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि वीरभद्र सरकार पठानिया को हटाएगी या नहीं। बीते रोज सचिवालय में इस मसले को लेकर बैठक हुई।

बताते हैं कि फाइल सीएम तक नहीं गई है। कुलदीप पठानिया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बेहद लाडले हैं। लेकिन एनजीटी का ये आदेश दोनों के लिए बड़ा झटका हैं। सूत्र बताते है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सरकार उनको हटाने के मूड़ में नहीं हैं व एनजीटी के आदेश की कानूनविदों से समीक्षा कराई जा रही हैं।

पठानिया चंबा जिला के भटियात से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। 2012 में वो भाजपा प्रत्याशी बिक्रम जरियाल से हार गए थे। बीते दिन वीरवार को एनजीटी के इस आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में बैठकों का दौर चला। लेकिन आदेश में असल में कहा क्या गया है ये साफ नहीं हो रहा था। बोर्ड के आला अफसर कह रहे हैं कि अभी क्लेरिटी नहीं हैं।

बहरहाल बोर्ड के कई अफसर जो बीते रोज तक उनके लाडले होने का स्वांग रचते थे वो ये खुशी से ये कहते हुए सुने गए कि 'गया, चेयरमैन गया',। बहरहाल उनकी कुर्सी पर अभी सस्पेंस बना हुआ हैं।

वीरभद्र के वॉकआउट के ड्रामे के बीच नरेंद्र चौहान बने नए मुख्य सूचना आयुक्त

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक का बहिष्कार करने और मुख्यमंत्री वीरभद्र का बीच बैठक से उठकर चले जाने के ड्रामे के बीच वरिष्ठ आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव नरेंद्र चौहान को मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी मिल गई हैं।

सचिवालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए सीआईसी को नियुक्त करने के लिए बुलाई गई बैठक में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल शामिल नहीं हुए। इस बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व मंत्री विद्या स्टोक्स बैठें। सूत्र बताते है कि इस बीच हिमाचल पब्लिक सर्विस कमिशन के हाल ही में रिटायर हुए चेयरमैन व वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी खजान सिंह तोमर को सीआईसी बनाने के मसले पर धूमल से हामी मांगी गई। सूत्र बताते है कि धूमल ने तोमर के नाम को इंकार कर दिया।

इसके बाद अफसरों ने नई सूची वीरभद्र व विद्या स्टोक्स के सामने रखी गई, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी वीसी फारका का नाम देखकर वो नाराज हो गए बैठक से उठकर चले गए। तब विद्या स्टोक्स अकेली ही रह गई। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी नरेंद्र चौहान जो 2018 में मार्च में रिटायर होने हैं के नाम को आगे किया गया। इस पर किसी ने कोई आपति नहीं जताई तो उन्हें प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी एक अरसे से खाली थी। इसके बाद आयोग केवल एक ही सदस्य के.डी. बातिश के सहारे चल रहा था। बीते दिनों वो भी रिटायर हो गए थे। ऐसे में सूचना आयोग खाली था।

बताते हैं कि इस पद पर विराजमान होने के लिए खजान सिंह तोमर एक अरसे से ताकत लगाए हुए थे। धूमल को मनाने के भी कई प्रयास हुए। इसके लिए धूमल के करीबियों को काम पर लगाया गया। लेकिन धूमल नहीं माने। तोमर पत्रकार रह चुके हैं। वीरभद्र के साथ नजदीकियां होने के कारण उन्हें पब्लिक सर्विस कमिशन का चेयरमैन लगा दिया गया था। उनका कार्याकाल कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ था। लेकिन वो और नौकरी चाहते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

सीआईसी के पद पर चीफ सेक्रेटरी वी.सी.फारका भी नजर गढ़ाए हुए थे। बताते है कि विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगने पर उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव रह चुके हैं। ऐसे में चुनावों के दौरान ऐसे व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीब रहा हो को, चीफ सेक्रेटरी के पद पर रखना चुनाव आयोग को आपतिजनक लग सकता है। अगर किसी ने इस बावत आयोग से शिकायत कर दी तो आयोग संज्ञान लेकर उन्हें हटा सकता हैं। फारका को हटाने के पीछे पहले ही उनसे सीनियर आईएएस विनीत चौधरी पूरा जोर लगाए हुए हैं।

10 श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए दूसरी देवी के पास

शिमला/कांगड़ा। पंजाब के अमृतसर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित मशहूर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी से वापस जिला कांगड़ा के दूसरे मशहूर शक्ति पीठ ज्वालामुखी में देवी के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस के सड़क हादसे का शिकार होने से उसमें सवार दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 30 के करीब यात्री जख्मी हुए है जिसमें अधिकतर को टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया हैं। हादसा ढलियारा के समीप हुआ हैं।

हादसा सुबह के वक्त हुआ हैं। ये श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर में मत्था टेकने के बाद ज्वालामुखी में मां ज्ध्वाला के दर्शन करने आ रहे थे। लेकिन रास्ते में बस सड़के के नीचे लुढक गई। न्यू मालवा ट्रैव्ल्ज की इस बस के हादसाग्रस्त के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य चलाया। लेकिन तब तक दस लोगों की लाशें इधर–उधर बिखर चुकी थी। हादसे में बचे यात्री अपने साथियों की लाशें अपने आस –पास देखकर सदमे में आ गए। स्थानीय लोगों व सरकारी अमले ने उन्हें जैसे–कैसे संभाला व अस्पताल पहुंचाया।

एसपी कांगड़ा संजीव गांधी ने कहा कि घायलों को देहरा व टांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। पुलिस के मुताबिक अधिकतर यात्री अमृतसर के कारोबारी व उनके परिवार के सदस्य थे। हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के निधन पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शोक व्यक्त किया हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हिदायतें दी हैं कि प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। पिछली साल भी ज्वालामुखी में आ रहे यात्रियों में से सात श्रद्धालुओं की ऐसे ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये सारे अमृतसर के ही थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

जनादेश के बाद रणनीति में भी भाजपा भारी पड़ी कांग्रेस पर

मेयर और डिप्टी मेयर पर भाजपा का कब्जा तय

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार करवा लिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार 19 जून को नये हाऊस का गठन हो गया है लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण इसके महापौर और उपमहापौर का चुनाव

नही हो सका है। इसके लिये 20 जून को फिर हाऊस की बैठक बुलाई गयी है। निगम के हाऊस का गठन पार्षदों के साथ शपथ लेने के साथ पूरा हो गया है। प्रशासन की जिम्मेदारी 19 जून तक हाऊस का गठन करने की थी लेकिन हाऊस के गठन के बाद इसके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। इसको लेकर एक्ट मे कुछ स्पष्ट नही है। बल्कि चार जून को पिछले सदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद 19 जून तक निगम की वैधानिक स्थिति क्या है इसको लेकर भी एक्ट में कुछ स्पष्ट नही है। क्योंकि नगर परिषदों के लिये तो एक्ट में यह प्रावधान है कि चयनित हाऊस की गैर मौजूदगी में इस पर प्रशासक नियुक्त हो जाता है। नगर परिषद् ठियोग में काफी समय तक इसके प्रशासक की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार के पास रही है जबकि परिषद् में सचिव स्थायी तौर पर नियुक्त था। किन्तु नगर निगम के संद्धर्भ में एक्ट के अन्दर प्रशासक का कोई प्रावधान नही किया गया है। नगर निगम का आयुक्त प्रशासक की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, क्योंकि वह तो निगम का अधिकारी होने के नाते हाऊस को जवाबदेह है। इसलिये जो निगम के हाऊस को जवाबदेह है वह उसका प्रशासक नही हो सकता। इसी के साथ एक्ट में यह भी स्पष्ट नही है कि यदि पार्षदों की संख्या दो भागों में बराबर-बराबर हो जाये तो उस स्थिति में क्या होगा। निगम की वैधानिकता को लेकर इस बार शहरी विकास विभाग ने चार जून को बनी स्थिति पर सरकार से निर्देश मांगे थे। सचिवालय में फाईल विधि विभाग को राय के लिये भेज दी लेकिन विधि विभाग ने कोई स्पष्ट राय देने के स्थान पर राज्य चुनाव आयोग के विचार जानने की सलाह दे दी। चुनाव आयोग ने यह कहकर निपटारा कर दिया कि एक्ट में इस बारे में कुछ नही कहा गया है।

स्मरणीय है कि निगम के चुनाव नियमों में भाजपा और कांग्रेस दोनो के शासनकालों में संशोधन हुए है। जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान से करवाया गया था। तब चुनाव नियमों में संशोधन हुआ। अब जब 11.2.2016 को पुन: नियमों में संशोधन करके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से करवाने की अधिसूचना जारी की गयी तब भी एक्ट की इन कमीयों की ओर ध्यान नही दिया गया। बल्कि इस बार जब चुनावों को लेकर मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा जब भी इस ओर ध्यान नही दिया गया। अब 11.2.2016 को अधिसूचित हुए चुनाव नियमों के अनुसार इस बार मेयर का पद पहले आधे कार्यकाल के लिये अनुसूचित जाति को जायेगा। उसके बाद बाकी बचे आधे कार्यकाल में यह पद अनुसूचित जनजाति को जायेगा। उसके अगले कार्यकाल में पहले अर्द्ध में सामान्य वर्ग को जायेगा और शेष अर्द्ध में महिला के लिये होगा। यह महिला सामान्य और रिजर्व किसी भी वर्ग से हो सकती है। इस पर भी नियमों में पूरी स्पष्टता नही है। क्योंकि यदि फिर यह चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से करवाने का फैसला लेकर नियमों में संशोधन किया जाता है उस स्थिति में रोस्टर प्रावधान का क्या होगा इस पर भी नियमों में कुछ स्पष्ट नही है। For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'' 12 Reservation and rotation of the office of Mayor- (1) The reservation for the office of Mayor shall be as under:-

(i) During the first two & half years SC

(ii) During the Second two & half years ST

(iii) During the next two & half years Gerenal

(iv) During the next two & half years Woman

Provided that where the population of any class of persons referred to above is less than fifteen percent of the total population of the Corporation area, the office of Mayor shall not be reserved for that class and same shall be thrown open to all the categories.

इस बार जब निगम में वार्डो की संख्या बढ़ाकर 34 की गयी थी उस समय यह चिवार नही किया गया कि चुनाव परिणाम में पक्ष और विपक्ष में बराबर संख्या होने पर क्या किया जायेगा। इस बार यह पार्टी चिन्ह पर नही हुए हैं और उस दृष्टि से सभी एक प्रकार से निर्दलीय हैं। कब कौन पासा बदल ले इसकी संभावना ऐसे खंडित जनादेश में बराबर बनी रहती है। कोई भी दल अपने सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई नही कर पायेगा क्योंकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हुए हैं। इस बार भाजपा ने कांग्रेस को जनादेश में हराकर मेयर के लिये रणनीति में भी करारी हार दे दी है। लेकिन इस तरह से जुटाये गये बहुमत को संभाले रखना भी आसान नही होता है क्योंकि ऐसी रणनीति के केन्द्र में सिन्द्धातो के स्थान पर सत्ता रहती है और सत्ता का लालच खतरनाक सिद्ध होता है। इस परिदृष्य में यदि भाजपा निगम

एक्ट की कमीयों को सुधारने में सफल हो जायेगी तो भविष्य की ऐसी सारी संभावनाएं समाप्त हो सकती है अन्यथा हर बार यह खतरे बने रहेंगे।

31 साल में पहुंची भाजपा नगर निगम की सत्ता तक

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला की सत्ता पर काविज होने के

लिये स्पष्ट बहुमत का 18 पार्षदों का आंकड़ा भाजपा अपने दम पर हालिस नही कर पायी है। सत्ता के लिये वह निर्दलीय पार्षदों पर आश्रित है। तीन निर्देलीय पार्षदों में से कितनों का समर्थन उसे मिल पाता है यह आने वाला समय ही बतायेगा। भाजपा पहली बार निगम में सत्ता के इतने निकट पहुंची है। इन चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव आयेंगे इस नाते इन चुनावों का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। संभवत: इसी महत्व को भांपते हुए इन चुनावों से पहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की शिमला में रैली आयोजित की गयी थी। मोदी की रैली के बाद अमित शाह और कई दूसरे बडे नेता भी किसी न किसी बहाने शिमला आये। स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा तो निगम चुनाव के प्रचार में भी आये। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मीडिया को अपने साथ रखने के लिये इसके कुछ लोगों को पालमपुर और दिल्ली ले जाकर केन्द्रिय नेतृत्व से भेंट करवाई गयी। भाजपा की यह रणनीति विधानसभा में 60 का आंकड़ा पाने के घोषित दावे के परिदृश्य में थी लेकिन इतने सघन प्रचार के बावजूद भाजपा का 34 में से 17 सीटों पर आकर रूक जाना यह इंगित करता है कि अब मोदी लहर संभवत: पहले जैसी नही रही है। यदि लहर होती तो भाजपा का आंकड़ा 30 तक पहुंचता। भाजपा की इतनी सफलता के लिये भी कांग्रेस में वीरभद्र -सुक्खु द्वन्द जिम्मेदार है यदि द्वन्द न होता तो सत्ता फिर कांग्रेस के पास जा सकती थी।

इस चुनाव में भाजपा को उन वार्डो में असफलता का मुह देखना पड़ा है जो पूरी तरह व्यापारी वर्ग के प्रभुत्व वाले थे। इन वार्डो में भाजपा की हार का अर्थ है कि अब यह वर्ग पार्टी के हाथ से निकलता जा रहा है। इस वर्ग में जीएसटी को लेकर रोष व्याप्त हो गया है जो आने वाले समय में बढ़ सकता है। इसी के साथ इस चुनाव में यह भी सामने आया है कि जिन वार्डो में जगत प्रकाश नड्डा प्रचार के लिये गये थे वहां पर भी पार्टी को सफलता नही मिली है। जबकि नड्डा को प्रदेश का अगला नेता प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में इस असफलता का एक ही अर्थ है कि या तो नड्डा को प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं का पूरा सहयोग नही है या फिर जनता में उनकी स्वीकार्यता नही बन पा रही है। इस चुनाव के प्रचार में पार्टी के नेताओं ने वीरभद्र के खिलाफ चल रहे मामलों का भी जिक्र तक नहीं उठाया जबकि चुनाव से पहले तक मुख्यमन्त्री से त्यागपत्र की मांग की जा रही थी। क्या भाजपा को इन आरोपों की विश्वसनीयता पर स्वयं ही अब विश्वास नही रहा है।

भाजपा यदि इस चुनाव प्रचार के अन्तिम दिन धूमल को फील्ड में न उतारती तो इतनी सफलता भी उसे न मिल पाती क्योंकि धूमल से पहले वीरभद्र ने शिमला ग्रामीण से जुडे वार्डो में जाकर स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया था। लेकिन धूमल ने अन्तिम दिन जाकर पूरा पासा ही पलट दिया। धूमल के अन्तिम दिन के प्रचार के कारण ही भाजपा को उन पांच वार्डो में सफलता मिली जो कांग्रेस के पक्के गढ़ माने जाते थे। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि भापजा को विधान सभा चुनावों के लिये नेतृत्व के प्रश्न पर शुरू से ही दो टूक फैसला प्रदेश की जनता के सामने रखना होगा। सामुहिक नेतृत्व की रणनीति से भाजपा को लाभ मिलना आसान नही होगा।

सरकार और वीरभद्र की

.....पृष्ठ 1 का शेष

फिर यह मामलें अपने आप ही कमजोर पड़ते चले गये। यही कारण है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने धूमल शासन के खिलाफ 'हिमाचल ऑन सेल' का आरोप लगाकर सरकार की छवि पर भ्रष्टाचार का जो 'टैग' चिपका दिया था। उस बारे में सत्ता में आकर कुछ किया ही नहीं गया। अपने ही लगाये आरोपों को प्रमाणित न कर पाने से वही टैग आरोप लगाने वालों पर चिपक जाता है। आज वीरभद्र प्रशासन की छवि के साथ अराजकता और भ्रष्टता के जो टैग चिपकते जा रहें है उसके लिये अधिकारियों का यही वर्ग जिम्मेदार है। यदि वीरभद्र समय रहते न संभले तो आने वाले समय में ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अभी भी संभलने का वक्त है क्योंकि इस चुनाव ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि आज की तारीख में मोदी लहर का असर प्रदेश में नही है।